

पांच प्रतिशत तक सस्ते हो सकते हैं मोबाइल फोन

सरकार ने मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े उपकरणों पर **आयात शुल्क** घटाकर 10 प्रतिशत किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: अंतरिम बजट से ठीक एक दिन पहले बुधवार को सरकार ने मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कई कंपोनेंट्स यानी उपकरणों पर आयात शुल्क में पांच प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। सरकार के इस फैसले से आने वाले समय में भारत में निर्मित मोबाइल फोन की लागत तीन से पांच प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। इससे मोबाइल फोन की कीमत में भी इतनी ही कमी आ सकती है। घरेलू स्तर पर मोबाइल फोन की निर्माण लागत कम होने से मोबाइल फोन के आयात की गुंजाइश कम हो जाएगी। साथ ही विदेशी कंपनियां भी भारत में मोबाइल बनाने के लिए और अधिक आकर्षित होंगी।

चीन, वियतनाम जैसे देशों में निर्माण लागत भारत के मुकाबले अब भी कम है। इससे विदेशी कंपनियां उन देशों में निर्माण करने के लिए आकर्षित होती हैं। हालांकि, सरकार के इस फैसले से मोबाइल उपकरण निर्माण इकोसिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। इस कदम से

• सरकार के इस कदम से घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को मिलेगा प्रोत्साहन

• चीन और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबले के लिए लिया गया फैसला



राजस्व के लिहाज से शीर्ष कंपनी रही एपल

नई दिल्ली, प्रेटर: कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान राजस्व के लिहाज से आइफोन निर्माता कंपनी एपल भारतीय बाजार में पहली बार शीर्ष पर रही है। वहीं, संख्या के लिहाज से सैमसंग शीर्ष पर रही है। काउंटरपाइंट रिसर्च की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 के दौरान भारत में स्मार्टफोन की थोक बिक्री 15.2 करोड़ इकाई पर स्थिर रही है। बीते वर्ष भारतीय बाजार में सैमसंग, वीवो और ओप्पो की हिस्सेदारी बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, बीते वर्ष एपल ने भारत में एक करोड़ इकाई की बिक्री का आंकड़ा भी पार किया है।

आयातित उपकरण सस्ता होने पर घरेलू निर्माण के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। वित्त मंत्रालय ने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े बैटरी कवर, मेन लेंस, बैक कवर, एंटीना, सिम शाकेट व अन्य मैकेनिकल उत्पादों के आयात शुल्क

को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तक करने का फैसला किया है। मोबाइल फोन से जुड़ी रिसर्च कंपनी काउंटरप्वाइंट के निदेशक तरुण पाठक ने बताया कि आयात शुल्क में कमी से फोन निर्माण लागत में 3-5 प्रतिशत की कमी तो आएगी,

10 हजार रुपये से कम मूल्य वाले फोन की बढ़ सकती है बिक्री



13.9 अरब डालर के फोन का निर्यात हुआ भारत से पिछले वर्ष



भारत में बिकने वाले 98 प्रतिशत फोन मेड इन इंडिया

वर्तमान में भारत में बिकने वाले 98 प्रतिशत फोन मेड इन इंडिया हैं। भारत में एक अरब से अधिक लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल फोन निर्माण व निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) योजना की घोषणा की थी, जिसके बाद से मोबाइल फोन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 13.9 अरब डालर के फोन का निर्यात किया था।

ज्यादा शुल्क से बढ़ रही थी मैन्यूफैक्चरिंग लागत

इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रानिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्र ने बताया कि कंपोनेंट्स पर आयात शुल्क अधिक होने से घरेलू स्तर पर बनने वाले फोन की लागत अधिक हो रही थी। इससे कंपनियां फोन की कीमत बढ़ा सकती थी। ऐसा होने पर सस्ते मोबाइल फोन का आयात बढ़ सकता था जिससे घरेलू फोन निर्माण पर प्रतिकूल असर पड़ता। इसलिए फोन निर्माता कंपनियों की तरफ से कंपोनेंट्स के आयात शुल्क में कटौती की मांग की जा रही थी।

लेकिन निर्माता कंपनी इसका कितना फायदा ग्राहकों को देती है, यह उन पर निर्भर करेगा। पुराना स्टॉक खत्म होने के बाद कंपनियां मोबाइल फोन की कीमत कम कर सकती हैं। अभी 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले फोन की बिक्री पहले के मुकाबले

कम हो गई है और कीमत में कमी से इनकी बिक्री बढ़ सकती है।

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पोस्ट में कहा कि सरकार के इस कदम से मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा।